



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1994/आषाढ़ 15, 1916

No. 94]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1994/ASADHA 15, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(बिफ्री कर विग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1994

फा० सं० 31/56/93-बि.क०.—दिनांक 27 मई, 1994 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें वित्त मंत्रियों की एक समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी जो कि मूल्यवर्धित कर लागू करने सहित, कर सुधार के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

2. इस संकल्प का अनुसरण करते हुए सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। हमने निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. वित्त मंत्री, महाराष्ट्र
2. वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश
3. वित्त मंत्री, केरल
4. वित्त मंत्री, तमिलनाडु
5. वित्त मंत्री, असम
6. वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश
7. वित्त मंत्री, पंजाब

8. वित्त मंत्री, पश्चिमी बंगाल

9. वित्त मंत्री, आन्ध्र प्रदेश

10. वित्त मंत्री, राजस्थान

11. वित्त मंत्री, दिल्ली

12. डा० राजा जे० खेन्सा

वित्तीय सलाहकार संयोजक

13. डा० महेश पुरोहित

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(क) “भारत में घरेलू व्यापार-करों के सुधार : मासले और बिकल्प” से संबंधित राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान की रिपोर्टें और पन्ध्रपण कर लगाने सहित उनकी सिफारिशों पर विचार करना।

(ख) केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों के बंटवारे के अनुकूल एकीकृत सुसमन्वित और कुशल अग्रत्यक्ष-कराधान पद्धति तैयार करना।

(ग) राज्य सरकारों और केन्द्र शामिल क्षेत्रों द्वारा विधान बनाकर लागू की जाने वाली मूल्य-वर्धित कर पद्धति की वांछनीयता व्यावहारिकता और संभव तमूने पर विचार करना।

(घ) समय-सीमा का गुंजाव देना जिसमें ऐसा मूल्य-वर्धित कर लागू किया जा सकता है।

- (ङ) एक आदर्श मूल्य-वर्धित कर विधेयक तैयार करना ।
 (घ) कर की दरों में एकस्यता और अन्य मामलों के बारे में दिनांक 27-5-94 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में हुए सल्लेख को कार्यान्वित करने के लिए तौर-तरीके और समय-सीमा का सुझाव देना ।

(छ) अन्य संबंधित मामलों के बारे में सिफारिशें करना ।

4. समिति अपने कार्य के लिए अपनी कार्यविधि तैयार करेगी और अपने अध्ययन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ शामिल क्षेत्रों से वह सूचना संग्रह करेगी जो कि आवश्यक होगी ।

5. समिति अपने कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है ।

6. राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति मन्थन समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करेगा ।

7. समिति 31 दिसम्बर, 1994 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

एम०आर० शिवरामन, सचिव (राजस्व)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Sales Tax Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th July, 1994

F.No. 31/56/93-ST.—The Finance Ministers' Conference held on 27th May, 1994 had adopted a resolution recommending Constitution of a committee of Finance Ministers to go into all the aspects of tax reform including introduction of the Value Added Tax.

2. In pursuance of this resolution the Government has decided to appoint a committee for this purpose. It will consist of—

1. Finance Minister of Maharashtra.
2. Finance Minister of Madhya Pradesh.
3. Finance Minister of Kerala.
4. Finance Minister of Tamil Nadu.
5. Finance Minister of Assam.
6. Finance Minister of Uttar Pradesh.
7. Finance Minister of Punjab.
8. Finance Minister of West Bengal.
9. Finance Minister of Andhra Pradesh.
10. Finance Minister of Rajasthan.

11. Finance Minister of Delhi.

12. Dr. Raja J. Chelliah,
Fiscal Adviser, Convenor.

13. Dr. Mahesh Purohit,
NIPF&P, Secretary.

3. The terms of reference of the Committee will be :—

(a) To examine the NIPF&P Report on "Reform of Domestic Trade Taxes in India : Issues and options" and their recommendations, including the levy of a consignment tax.

(b) To evolve an integrated, well coordinated and efficient system of indirect taxation consistent with the division in fiscal powers between the Centre and the States.

(c) To consider the desirability, feasibility and the possible design of a Value Added Tax system to be introduced by the State Governments and Union Territories with legislature.

(d) To suggest a time frame within which such a VAT could be introduced.

(e) To prepare a model VAT legislation.

(f) To suggest modalities and a time frame to implement the consensus reached in the Finance Ministers' Conference held on 27-5-1994 about uniformity in tax rates and other matters.

(g) To make recommendation regarding any other related matters.

4. The Committee will evolve its own procedures for its work and may for its study call for information as may be necessary from Central and State Governments/Union Territories.

5. The Committee may co-opt any other expert as a member to facilitate its work.

6. The NIPF&P will provide secretarial assistance to the Committee.

7. The Committee will submit its report by the 31st December, 1994.

M. R. SIVARAMAN, Secy. (Revenue)